Impact of foreign participation in Telecom Sector as India's Security Interest

2284. DR. BIPLAB DASGUPTA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the issue of country's defence and security interests, has been examined by any committee or group of Defence, Security Intelligence and policy planning in the light of proposed foreign equity participation in the basic telecom services;

(b) if so, when and what urgent steps will be taken in this direction; arid

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) Adequate safeguards have been provided in the tender document and the licence agreement. The safeguards have been formulated in consultation with the Ministry of Home Affairs.

रेल डिब्बों का निर्यात

2285. **श्री अजीत जोगी**:

श्रीमती वीणा वर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)विश्व भारत विश्व के अनेक देशों को रेल डिब्बों का निर्यात करता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के दौरान प्राप्त हुए निर्यात आदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वदेशी बाजार और निर्यात के लिए रेल डिब्बों के उत्पादन की गुणवंत्ता में सुधार के लिये क्या – क्या कदम उठाये जा रहे है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान प्राप्त हुए निर्यात आदेशों का ब्यौरा इस प्रकार है:

1992-93 - कोई नहीं

1993-94 – मै. जेस्सप. उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम ने वियतनाम रेलवे से निम्नलिखित निर्यात आदेश प्राप्त किए थे:

1 मीटर लाइन के 9 अदद सवारी डिब्बे तथा

2 मीटर लाइन की 40 अदद सवारी बोगियां ।

1994-95 : भारतीय रेल की उत्पादन इकाइयों ने निम्नलिखित निर्यात

1. नेपाल रेलवे से छोटी लाइन के 6 अदद सवारी डिब्बे, तथा

2. वियतनाम रेलवे से मीटर लाइन के 15 अदद सवारी डिब्बे (10 अदद वातानुकूल तथा 5 अदद साधारण)

(ग) गुणवत्ता में सुधार करना एक सतत प्रकिया है तथा कर्मचारी कुशलता, निवेश सामग्री की गुणवत्ता में सुधार तथा सवारी डिब्बों की गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया के लिए प्रयास किए जाते हैं।

मध्य प्रदेश में जंगली हाथियों को पकड़ने पर खर्च हुई धनराशि

2268. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश में जंगली हाथियों को पकड़ने में कितनी धनराशि खर्च कि गई है और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई हैं।

(ख) उपर्युक्त वर्षो के दौरान पकड़े गए हाथियों के रख-रखाव पर राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च कि गई है;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान जंगली हाथियों द्वारा जान-माल का कितना नुकसान किया गया और इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को समस्या के स्थाई समाधान हेतु राज्य में किसी स्थान पर हाथी अभयारण्य बनाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने दो वर्षो 1993-94 में 17.294 लाख ओर 1994-95 में 34.15 लाख रूपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार को सी. सी.एस परियोजना के तहत हाथियों को पकड़ने और